The Government of India have not received any report about the agitation by Veterinary Doctors etc. in Mysore.

खाद्य क्षेत्र

89. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य क्षेत्र समाप्त करने के विषय पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) वर्तमान खाद्य क्षेत्रों को जारी रखने की आवश्यकता अथवा अनावश्यकता की समीक्षा समय समय पर राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के परामर्श से की जाती है । अगली बार समीक्षा करने की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गयी है । अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस मामले में कोई नया निर्णय, यदि कोई हुआ तो, कब लिये जाने की सम्भावना है ।

Flour Mills in Assam

90. **Dr. Sarojini Mahishi:** Will the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation be pleased to state:

(a) the particulars of the flour mills which were set up in Assam last year and are now ready to go into production;

(b) whether it is a fact that Government have not so far sanctioned them quota of wheat for trial run and grinding purposes; and

(c) if so, the steps being taken to expedite the matter and thus utilise the idle capacity?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon): (a) 1 M/s. Jyoti Flour Mills. Nowgong; and 2. M/s. Biswanath Flour Mills, Tinsukia.

(b) and (c). Milling licences under the Wheat Roller Flour Mills (Licensing & Control) Order, 1957, to these two flour mills are under issue. Ad-hoc quota of wheat for test grinding will be issued after the terms and conditions governing the sale of imported wheat are accepted by the mills and other necessary formalities are completed.

राज्यों में रबी की फसलों का बोया जाना

91. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1964–65 में विभिन्न राज्यों में कितनी भूमि में रबी की फसलें उगाई गई थीं ;

(ख) इस वर्ष कितनी भूमि में रबी की फसलें उगाई गई ; और

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने किसानों को किस प्रकार प्रत्यक्ष सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) एक विवरण (अनुबन्ध 1) सभा पटल पर रखा गया है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या LT— 5434(i)/66]

(ख) अभी तक 1965–66 की रबी की फसलों के अन्तर्गत आई फसलों के क्षेत्र का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । फिर भी, राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के